

## प्रखर नीति निर्माण के लिए समयबद्ध और प्रासंगिक सांख्यिकी\*

डॉ. पूनम गुप्ता

सुप्रभात, डॉ. महेंद्र देव, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, डॉ. सौरभ गर्ग, सचिव सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अधिकारी, साथी अर्थशास्त्री गण और साथी नीति निर्माता। इस प्री-रिलीज़ कंसल्टेटिव वर्कशॉप का हिस्सा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

मैं भारत की प्रमुख समष्टि आर्थिक आंकड़ा श्रृंखला के आधार संशोधन की प्रक्रिया में विश्वसनीयता, स्वामित्व और उत्साह लाने में डॉ. सौरभ गर्ग के नेतृत्व को श्रेय देना चाहूंगी। मैं इस अभ्यास में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी स्वीकार करना चाहती हूँ, जिनमें से कई आज यहां उपस्थित हैं। डेटा और आंकड़े सार्वजनिक वस्तुएं हैं। संशोधित श्रृंखला बनाने में मदद करने में, आप सभी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं।

हमारी सांख्यिकीय प्रणाली में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और पद्धतिगत कठोरता की एक लंबी परंपरा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) सरकारों, व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और परिवारों द्वारा निर्णय लेने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से हैं। इसलिए, इन श्रृंखलाओं का आधार संशोधन केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, यह व्यापक समुदाय के लिए मूलभूत महत्व का है। अर्थव्यवस्था के अधिक विविध और डिजिटल होने के साथ, बढ़ती समृद्धि, जनसांख्यिकीय बदलाव, उपभोक्ता वरीयताओं को विकसित करने और गहन वित्तीय समावेशन के साथ, हमारी खपत और उत्पादन बास्केट तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं है।

\* 26 नवंबर, 2025 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), मुंबई के आधार संशोधन पर प्री-रिलीज़ कंसल्टेटिव वर्कशॉप में दिया गया भाषण। आनंद शंकर, सोमनाथ शर्मा, धीरेन्द्र गजभिये, जीवी नाधनेल, जॉन वी गुरिया, पल्लवी चव्हाण और तुषार बी दास से प्राप्त सहायता और एआर जोशी, इंद्रनील भट्टाचार्य और संगीता मिश्रा से प्राप्त टिप्पणियों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

इसके साथ ही, जिस तरह से हम उत्पादन, बाजार, वितरण, और वित्त उपभोग और निवेश भी विकसित कर रहे हैं। वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं फिर से संगठित हो रही हैं। परिवारों की बचत और निवेश की आदतें बदल रही हैं, साथ ही वित्तीय मध्यस्थता के तरीके भी बदल रहे हैं। इन सभी का इस बात पर असर पड़ता है कि हम क्या बनाते हैं और हम अपनी प्रमुख मैक्रो डेटा श्रृंखला का निर्माण कैसे करते हैं।

अपनी टिप्पणी में, मैं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में की जा रही कुछ पहलों को संक्षेप में बताऊंगी ताकि इन अंतर्निहित बदलावों को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वयं के आंकड़ों और सांख्यिकीय पेशकशों को बढ़ाया जा सके।

आरबीआई के डेटा पेशकशों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई दैनिक से लेकर वार्षिक तक की आवृत्तियों पर बड़ी मात्रा में आर्थिक और वित्तीय डेटा का दस्तावेजीकरण, संकलन और प्रसार करता है। यह न केवल एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि कभी-कभी बैंकिंग, भुगतान संतुलन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, राज्य वित्त, नगरपालिका वित्त और पंचायती राज संस्थानों के वित्त पर व्यापक डेटा का एकमात्र स्रोत है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इन आंकड़ों को प्रेस विज्ञप्तियों, अपने प्रमुख प्रकाशनों के साथ-साथ अपने डेटा पोर्टल, डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी (डीबीआईई) पर समय पर अपडेट के माध्यम से तुरंत प्रसारित करता है।

दूसरा, इस तरह के 'हार्ड डेटा' के अलावा, आरबीआई घरों, कॉरपोरेट्स, बैंकों और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के आठ भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण (तिमाही पर चार और द्वि-मासिक आवृत्ति पर चार) आयोजित करता है, जिसमें मुद्रास्फीति की उम्मीदों, उपभोक्ता विश्वास और क्षेत्रीय दृष्टिकोण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।<sup>1</sup> ये सर्वेक्षण आर्थिक गतिविधियों और भावनाओं

<sup>1</sup> इनमें शामिल हैं - बैंक ऋण सर्वेक्षण; विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण; iii. परिवारों का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण; iv. विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूस; v. ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण; vi. सेवा और अवसंरचना आउटलुक सर्वेक्षण; vii. वृहद आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण; और आठवां शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण।

में बदलाव के शुरुआती संकेत प्रदान करते हैं। वे नीतिगत विचार-विमर्श में इनपुट के रूप में काम करते हैं और साथ ही 'कठिन' आंकड़े उपलब्ध होने से पहले ही व्यापक समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हैं।

अंत में, मौद्रिक नीति का संचालन करने के अपने अधिदेश के एक भाग के रूप में, जो लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था (एफआईटी) के तहत भविष्योन्मुखी है, आरबीआई अपनी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति घोषणाओं में मुद्रास्फीति और विकास पूर्वानुमान तैयार करता है और जारी करता है।<sup>2</sup>

मैं इनमें से प्रत्येक पेशकश में हमारी हाल की कुछ पहलों का संक्षेप में वर्णन करती हूँ।

**आरबीआई द्वारा प्रकाशित 'हार्ड' डेटा से संबंधित हालिया पहल**

(i) भारतीय रिजर्व बैंक प्रशासनिक और विनियामक रिपोर्टिंग आंकड़ों के एक बड़े निकाय का संकलन करता है जो इसे विनियमित और अन्य कंपनियों से सीधे प्राप्त होता है। इनमें बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न, सुपरवाइजरी रिटर्न, लिक्विडिटी और कैपिटल पर्याप्तता मेट्रिक्स, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) से लेकर यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी पेमेंट डेटा तक की जानकारी शामिल है। हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे समय पर, बारीक और उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा की मांग बढ़ी है, आरबीआई ने अपनी डेटा प्रसार प्रणालियों को आधुनिक बनाने, कवरेज का विस्तार करने और उन्नत तकनीकों को अपनाने के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।

**भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस**, 2004 में आरबीआई के एकीकृत डेटा प्रसार मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। समय के साथ, डीबीआईई में कवरेज, कार्यक्षमता और पहुंच में निरंतर वृद्धि हुई है। यह अब 2,000 से अधिक सांख्यिकीय

सारणियों को होस्ट करता है, जिसमें वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय बाजारों, सार्वजनिक वित्त, बाहरी क्षेत्र, बैंकिंग सांख्यिकी, सर्वेक्षण और कॉर्पोरेट प्रदर्शन में फैली 20,000 से अधिक व्यक्तिगत डेटा श्रृंखला शामिल हैं। 2009 से, इसने डीबीआईई के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका का लगभग वास्तविक समय अपडेट प्रदान किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ताओं को नवीनतम जानकारी प्राप्त हो<sup>3</sup>

इसे समझदार, उपयोगकर्ता के अनुकूल और व्यापक बनाने के प्रयास निरंतर आधार पर जारी हैं। नियोजित संवर्द्धन में अंतर्निहित डेटा आर्किटेक्चर का नया स्वरूप, स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का विकास, बेहतर खोज और विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण, और पोर्टल, मोबाइल ऐप और भविष्य के डिजिटल चैनलों में सामंजस्यपूर्ण उपयोगकर्ता अनुभव शामिल हैं।

(ii) **भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों के प्रवाह और बकाया ऋण के आंकड़े** - भारतीय वित्तीय प्रणाली पारंपरिक रूप से काफी हद तक बैंक-प्रधान रही है। इसलिए, काफी उचित रूप से, बैंक ऋण वृद्धि को अब तक वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के प्रवाह और अर्थव्यवस्था के विकास दृष्टिकोण के लिए इसके निहितार्थ का आकलन करने के लिए एक प्रमुख पैरामीटर के रूप में देखा गया है।

तथापि, वित्त के गैर-बैंक स्रोतों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, बैंकों और गैर-बैंक स्रोतों (घरेलू और विदेशी सहित) से वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के प्रवाह के व्यापक स्पेक्ट्रम का आकलन आवश्यक हो गया है।

इस पृष्ठभूमि में, हमने वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह पर डेटा संकलित करना शुरू कर दिया है। गैर-बैंक स्रोतों में गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीधे मुद्रा और पूंजी बाजार में इक्विटी, वाणिज्यिक पत्र और कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से इन संस्थाओं को ऋण शामिल हैं। विदेशी वाणिज्यिक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

<sup>2</sup> रिजर्व बैंक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, मुद्रास्फीति और निर्यात और आयात सहित बाह्य क्षेत्र के विकास जैसे प्रमुख आर्थिक पैरामीटरों पर अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के आकलन और अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का द्वि-मासिक सर्वेक्षण भी करता है।

<sup>3</sup> इंटरफेस को उत्तरोत्तर परिष्कृत किया गया है। इसके अलावा, आरबीआई-डेटा, एक मोबाइल एप्लिकेशन, फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था।

वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए संसाधनों के अतिरिक्त स्रोत हैं। वास्तव में, 2024-25 के दौरान, वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल संसाधनों का आधे से थोड़ा कम (48.7 प्रतिशत) गैर-बैंक स्रोतों से जुटाया गया था।

आर्थिक गतिविधियों के लिए समग्र संसाधन प्रवाह का आकलन करने में इस जानकारी की प्रधानता को देखते हुए, इस महीने से हमने भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में दो सारणियों, अर्थात् भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रवाह और भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बकाया ऋण का प्रसार शुरू कर दिया है।<sup>4</sup> इन आंकड़ों को अब से मासिक आवृत्ति पर आरबीआई बुलेटिन में अपडेट और जारी किया जाएगा।

**(iii) अधिक समय पर और लगातार भुगतान संतुलन डेटा** - इसके अलावा, भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आंकड़ों की समय पर और अधिक लगातार उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए, तिमाही बीओपी आंकड़ों को जारी करने में समय अंतराल को 2025-26 की पहली तिमाही से शुरू करके 90 दिनों से घटाकर लगभग 60 दिन कर दिया गया है।<sup>5</sup> यह डेटा रिपोर्टिंग समय सीमा को अनुकूलित करके और आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके हासिल किया गया था।

आगे बढ़ते हुए, हम मासिक बीओपी आंकड़े तैयार करने और जारी करने का प्रयास करेंगे (यद्यपि थोड़ा अधिक समग्र-स्तर पर और लगभग 40 दिनों के अंतराल पर)। इसे प्राप्त करने के लिए, विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं की डेटा प्रोसेसिंग समयसीमा में तेजी लाई जा रही है और सुव्यवस्थित किया जा रहा है, और आगे आंतरिक सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।

<sup>4</sup> तीन वित्तीय वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र को बकाया ऋण सहित '2024-25 के दौरान भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रवाह' शीर्षक से एक लेख आरबीआई बुलेटिन के सितंबर 2025 अंक में प्रकाशित किया गया था। 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लिए 'भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह' (संशोधित प्रारूप के अनुसार) पर वार्षिक डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 पर सांख्यिकी की पुस्तिका में प्रकाशित किया गया था।

<sup>5</sup> यह डेटा कवरेज से समझौता किए बिना किया गया है। आईएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार डेटा को अलग-अलग स्तर पर जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ ने मार्च 2025 में इंटीग्रेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजिशन मैनुअल (बीपीएम7) [अपने पहले बीपीएम 6 से] के अपने 7वें संस्करण के जारी के साथ बीओपी संकलन मैनुअल को संशोधित किया है। इन अद्यतनों/विकासों के साथ, देशों को बीएमपी 7 ढांचे के अनुरूप अपने बीओपी और राष्ट्रीय खाते के आंकड़े प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

## आरबीआई के सर्वेक्षणों में हाल की पहल

इसके अलावा, आरबीआई अपने उद्यम और घरेलू सर्वेक्षणों को अपग्रेड कर रहा है। ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे (ओबीआईसीयूएस), और इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज आउटलुक सर्वे जैसे एंटरप्राइज सर्वे की व्यापक समीक्षा की जा रही है, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली लगभग एक दशक से काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। हम कवरेज का विस्तार करने, उभरते क्षेत्रों को शामिल करने, कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने और डेटा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समय-समय पर अपडेट की योजना बना रहे हैं।

मुद्रास्फीति की उम्मीदों और उपभोक्ता विश्वास पर घरेलू सर्वेक्षणों को पिछले दो वर्षों में अधिक शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विस्तारित किया गया है। हालांकि, उनकी व्यापक कार्यप्रणाली 2018 से अपरिवर्तित रही है। ये सर्वेक्षण कथित और वास्तविक मुद्रास्फीति के बीच के अंतर को दूर करने, प्रश्नावली डिजाइन में सुधार करने और घरेलू पैनेलों को शामिल करने का पता लगाने के लिए एक नए मूल्यांकन के दौर से गुजर रहे हैं।<sup>6</sup>

## हमारे मुद्रास्फीति और विकास पूर्वानुमानों में हाल की पहल

एफआईटी ढांचे के तहत, हमारा अधिदेश विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। चूंकि मौद्रिक नीति संचरण में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अंतराल के साथ संचालित होती है, इसलिए आज लिए गए निर्णय कई तिमाहियों में उत्पादन और मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, उसे न केवल वर्तमान स्थितियों के बारे में एक दृष्टिकोण बनाना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि निकट अवधि में अर्थव्यवस्था के होने की संभावना है।

<sup>6</sup> उद्यम सर्वेक्षणों के अपेक्षित परिणामों में (i) सर्वेक्षणों के कवरेज को बढ़ाना (ii) सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन उद्योग-समूहों जैसे उभरते उद्योग-समूहों को नमूना फ्रेम में शामिल करना (iii) सर्वेक्षण संकेतकों के एकत्रीकरण के लिए कार्यप्रणाली को संशोधित करना (iv) सर्वेक्षण प्रश्नावली को संशोधित करना, (v) दूसरों के बीच अधिक कठोर डेटा गुणवत्ता जांच को अपनाना। घरेलू सर्वेक्षणों के लिए अपेक्षित परिणामों में सर्वेक्षण प्रश्नावली के शब्दार्थ को बढ़ाना, फिर से लिखना और परिष्कृत करना शामिल है, और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं और परिवारों की आर्थिक भावनाओं को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए सर्वेक्षण डिजाइन (पायलट सर्वेक्षण के कई दौरों के आधार पर) के हिस्से के रूप में परिवारों के पैनेल को शामिल करने की संभावना शामिल है।

इसलिए, द्वि-मासिक एमपीसी संकल्प आगे चार तिमाहियों तक मुद्रास्फीति और विकास का पूर्वानुमान प्रदान करता है।<sup>7</sup>

किसी भी पूर्वानुमान अभ्यास, अपने स्वभाव से, पूर्वानुमान त्रुटियों को प्राप्त करने का जोखिम होता है।

ऐसी त्रुटियां दुनिया भर में एक आम विशेषता हैं। ये आम तौर पर बड़े होते हैं जब अप्रत्याशित आघात या घटनाएं होती हैं और जब कोई भविष्य में बहुत आगे की भविष्यवाणी कर रहा होता है तो बड़े होते हैं।<sup>8</sup> शोध से पता चला है कि अनिश्चितता की अवधि के दौरान पूर्वानुमानकर्ताओं में भिन्नता बढ़ जाती है।<sup>9</sup> सीपीआई बास्केट में खाद्य पदार्थों के उच्च और पुराने वजन और खाद्य कीमतों की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए, भारत में मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है।

इसलिए, हम मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने में एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसमें (i) संरचनात्मक और समय-श्रृंखला मॉडल के एक सूट का उपयोग करना शामिल है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर एक अलग लेंस प्रदान करता है; (ii) कीमतों में अंतर्निहित गति की पहचान करने के लिए आंकड़ों में ऐतिहासिक पैटर्न की जांच करना, और आधार प्रभावों का आकलन करना, जो अक्सर निकट अवधि की मुद्रास्फीति की गतिशीलता को आकार देते हैं; (iii) मांग, आपूर्ति और कीमतों पर उनके निहितार्थों में वास्तविक समय के उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों और सर्वेक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करना; (iv) टर्निंग पॉइंट्स, स्ट्रक्चरल ब्रेक और उभरते जोखिमों की व्याख्या करने के लिए विशेषज्ञ विचारों की तलाश करना जो अकेले मॉडल पूरी तरह से कैप्चर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

हम अपनी पूर्वानुमान सटीकता को लगातार बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक मॉडल और दृष्टिकोणों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार, हम उचित समय अवधि

<sup>7</sup> फरवरी एमपीसी संकल्प को छोड़कर, जहां अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति अनुमान के साथ मुद्रास्फीति के लिए 5 तिमाही आगे का अनुमान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियम (2016) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति और विकास और जोखिमों के संतुलन के अनुमानों को प्रस्तुत करना और अप्रैल और अक्टूबर में द्वि-वार्षिक रूप से जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में हमारे प्रक्षेपण प्रदर्शन का आकलन करना आवश्यक है।

<sup>8</sup> उच्च अस्थिरता के तहत मुद्रास्फीति पूर्वानुमान सटीकता: क्रॉस-कंट्री साक्ष्य मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2023 में बॉक्स 1.1, RBI

<sup>9</sup> पेशेवर मैक्रोइकॉनॉमिक पूर्वानुमानकर्ताओं के बीच अनिश्चितता और असहमति, आरबीआई बुलेटिन, नवंबर 2021।

का आकलन कर रहे हैं जिस पर हमें अपने मॉडलों में विचार करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम सुदूर अतीत की तुलना में अधिक हालिया और प्रासंगिक जानकारी का उपयोग करें। हमने अपने हितधारक परामर्श के दायरे को भी बढ़ाया है, जिसमें मौजूदा परामर्शों के एक विस्तृत कार्यक्रम के अलावा, हमने पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के एक घूर्णन सेट के साथ एक दिन की कार्यशाला को जोड़ा है ताकि हम एक-दूसरे से सीख सकें।

पूर्वानुमान त्रुटियों को कम करने के अलावा, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पूर्वानुमानों में कोई व्यवस्थित पूर्वाग्रह न हो। जहां तक एमपीसी संकल्प में उपयोग किए गए मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों का संबंध है, वे निष्पक्ष हैं। मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा पर हाल ही में जारी चर्चा पत्र से पता चलता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के दौरान भारत में मौद्रिक नीति समिति के मुद्रास्फीति के विचलन और विकास पूर्वानुमानों में वास्तविक मुद्रास्फीति और विकास से कोई व्यवस्थित दिशात्मक पूर्वाग्रह नहीं है।<sup>10</sup>

मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की तरह, आरबीआई अपने विकास अनुमानों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। आरबीआई अपने अनुमानों को तैयार करने में मजबूत अर्थमितीय विश्लेषण, समकालीन आर्थिक स्थितियों और दूरदेशी क्षेत्रीय दृष्टिकोण के संतुलित संश्लेषण पर निर्भर करता है। तकनीकी मॉडलों में, अनुमान किसी एक मॉडल के बजाय दृष्टिकोणों के एक सूट से प्राप्त होते हैं। इनमें बेंचमार्क संकेतक दृष्टिकोण, एक गतिशील कारक मॉडल और अल्पकालिक विकास अनुमानों के लिए विभिन्न समय श्रृंखला मॉडल शामिल हैं।<sup>11</sup>

प्रत्येक मौद्रिक नीति बैठक से पहले, हम वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय बाजारों, बैंकों, एनबीएफसी, विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों के हितधारकों के साथ लगभग एक दर्जन चर्चाएं करते हैं। ये

<sup>10</sup> अनुलग्नक 4: मुद्रास्फीति और विकास प्रक्षेपण विश्लेषण। मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा - एक चर्चा पत्र, आरबीआई, अगस्त 2025

<sup>11</sup> कई तरीकों का उपयोग आरबीआई के अनुमानों को मजबूती प्रदान करता है। बेंचमार्क संकेतक दृष्टिकोण, जो एनएसओ द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान प्राप्त करने से संबंधित है, का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कम करने के लिए किया जाता है। उच्च आवृत्ति संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला से संघनित कारकों को प्राप्त करने से संबंधित गतिशील कारक मॉडल का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को अभी तक करने के लिए भी किया जाता है। समय श्रृंखला मॉडल में एआरआईएमएक्स मॉडल (बहिर्जात चर सहित एआरआईएमएक्स मॉडल), और वीएआरएक्स मॉडल (अंतर्जात और बहिर्जात चर दोनों सहित वेक्टर ऑटोरेग्रेसिव मॉडल) शामिल हैं। एआरआईएमएक्स और वीएआरएक्स मॉडल एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि पहला एकल लक्ष्य चर (जीडीपी वृद्धि) पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि बाद वाला संयुक्त रूप से आपसी बातचीत के साथ कई चर मॉडल करता है।

इंटरैक्शन हमें उनके दृष्टिकोण, दृष्टिकोण और पूर्वानुमानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो हमारे आकलन को सूचित करते हैं। एनएसओ के साथ हमारी आवधिक बातचीत उल्लेखनीय है, क्योंकि वे आरबीआई के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

### समापन टिप्पणियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था रही है जिसने समुत्थानशीलता और लचीलापन दोनों का प्रदर्शन किया है। हमारी सांख्यिकीय पेशकश, डेटा और तकनीकों को

एक ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना चाहिए जो तेजी से बढ़ रही है और विकसित हो रही है। मौजूदा डेटा श्रृंखला को नियमित रूप से अपडेट और संशोधित करना, साथ ही नए लोगों का निर्माण करना, चल रहे परिवर्तनों को पकड़ने के लिए आवश्यक है। हम सभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही संशोधित श्रृंखला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर इस परामर्श प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को बधाई देती हूँ और कार्यशाला की सफलता की कामना करती हूँ।